

एंवागो : 13 दिसंबर, 2006 को वाशिंगटन, डीसी में प्रातः 12:01 बजे (जीएमटी प्रातः 5:01 बजे) के पहले प्रकाशित, प्रसारित या प्रेषित न करें।



THE WORLD BANK

Working for a World  
Free of Poverty

प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति सं. 2007/159/डीईसी

संपर्क:

वाशिंगटन में: मेरेल टक (202)473-9516

मोबाइल: (202) 415 1775

[mtuckprimdahl@worldbank.org](mailto:mtuckprimdahl@worldbank.org)

रेडियो/टीवी: नाज़नीन अताबाकी

(202) 458-1450

[Natabaki@worldbank.org](mailto:Natabaki@worldbank.org)

## वृद्धि की आशा मजबूत, मगर वैश्विकरण से उत्पन्न सामाजिक व पर्यावरणीय दबावों पर गौर करने की ज़रूरत

वाशिंगटन डीसी, 13 दिसंबर 2006 - आगामी 25 वर्षों में, वैश्विकरण के फलस्वरूप और 1980-2005 के मुकाबले, औसत आय में तेज़ गति से वृद्धि हो सकती है, और इसमें विकासशील देश केन्द्रीय भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यदि इस वृद्धि को ठीक से नहीं संभाला गया, तो विश्व बैंक का कहना है कि आय आधारित असमानताएं बढ़ सकती हैं और पर्यावरण पर गंभीर दबाव पड़ सकता है।

*Global Economic Prospects 2007: Managing the Next Wave of Globalization (2007 की वैश्विक आर्थिक संभावनाएं: वैश्विकरण की अगली लहर को संभालना)* के अनुसार, इस वर्ष विकासशील देशों में 7 प्रतिशत के आस-पास रिकार्ड वृद्धि होने की आशा है। 2007 तथा 2008 में यह वृद्धि धीमी हो सकती है, पर फिर भी, 6 प्रतिशत की सीमा को लांघ सकती है, यानि ऊँची आय वाले देशों की अपेक्षित 2.6 प्रतिशत वृद्धि दर से दोगुना अधिक वृद्धि।

अगले 25 वर्षों में वैश्विकरण विश्व की आर्थिक व्यवस्थाओं को क्या आकार देगा, इस संदर्भ में रिपोर्ट का "केन्द्रीय दृश्यलेख" यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2005 में 35 ट्रिलियन डॉलर के अपने प्रदर्शन से बढ़कर सन् 2030 तक 72 ट्रिलियन डॉलर का प्रदर्शन कर सकता है। रिपोर्ट के मुख्य लेखक और व्यापार विभाग के आर्थिक परामर्शदाता, रिचर्ड न्यूफार्मर कहते हैं "हालांकि पिछले 25 वर्षों की तुलना में वैश्विक वृद्धि में केवल कुछ ही अधिक गतिवर्द्धन हुआ है, उल्लेखनीय है कि विकासशील देशों के प्रबल प्रदर्शन ने इस संख्या में पहले से कहीं अधिक अंशदान किया है। आगे चलकर इन सटीक संख्याओं को बेशक कुछ-कुछ बदलना होगा, पर अंतर्निहित रुझानों को आसानी से बदला नहीं जा सकता – इन्हें बदलने के लिए कोई बहुत ही गंभीर या विच्छेदक धक्का लगना होगा।"

विकासशील देशों में लंबी अवधि के लिए आगर व्यापक आर्थिक वृद्धि होती रही, तो वैश्विक निर्धनता पर इसका महत्वपूर्ण असर पड़ेगा। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फ्रांस्वा बुर्गिन्यो का कहना है कि "प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीने वाले लोगों की संख्या 1.1 अरब से कम होकर 2030 तक 55 करोड़, यानि आधी हो जाएगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों को, खासकर अफ्रीका को, पिछड़ जाने का खतरा है। इसके अलावा, कई देशों के अंदर आय की असमानताएं और भी बढ़ सकती हैं, जिससे देशों के बीच असमानताओं को लेकर आज जो हमारी चिंताएं वे और भी गंभीर बन सकती हैं।"

माल और सेवाओं में वैश्विक व्यापार बढ़कर तिगुना हो सकता है, यानि 2030 तक 27 ट्रिलियन डॉलर, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार का हिस्सा आज के एक-चौथाई से बढ़कर एक-तिहाई बन जा सकता है। लगभग आधी वृद्धि विकासशील देशों का योगदान होगा। जबकि दो दशक पहले विकासशील देश धनी देशों को केवल 14 प्रतिशत निर्मित माल भेजा करते थे, आज इन देशों से 40 प्रतिशत निर्मित आयात मंगवाए जाते हैं, और 2030 तक, निर्मित मालों की 65 प्रतिशत आवश्यकता इन्हीं देशों से पूरी करवाई जाएगी। साथ-साथ, विकासशील देशों में आयातों की उभरती मांगें विश्व अर्थव्यवस्था के लिए चालक सिद्ध होगी।

बाजारों का एकीकरण होता जाएगा और विश्व के हर कोने में नौकरियों पर स्पर्धात्मक दबाव डलेगा। बैंक के 'विकास संभावनाएं समूह' के निदेशक यूरी दादुश ने समझाया कि "जैसे-जैसे विकासशील देशों में व्यापार का विस्तार होता जाएगा और प्रौद्योगिकी फैलती जाएगी, मजदूरों को - और निम्न स्तर के कुछ पढ़े-लिखे कर्मियों को भी - सीमा-पार से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान की नौकरियां बचाने का प्रयास न करके, सरकार को चाहिए कि वह अव्यवस्थित कर्मियों को समर्थन दे और उन्हें नए मौके प्रदान करे। शिक्षा में सुधार और श्रम-बाजार में लचीलापन लाना दीर्घकालिक समाधान की कुंजियां हैं।"

वैश्विकरण से बहुतों को लाभ होगा। 2030 तक विकासशील देशों में 1.2 अरब लोग - यानि विश्व की 15 प्रतिशत जनसंख्या - "वैश्विक मध्यवर्ग" के सदस्य बन जाएंगे, जहां आज इस वर्ग में केवल 40 करोड़ लोगों की गिनती की जा सकती है। इस समूह की क्रय शक्ति 4,000 और 17,000 डॉलर प्रतिव्यक्ति के बीच हो सकती है। इसके सदस्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करेंगे, मोटर तथा अन्य टिकाऊ व आधुनिक वस्तुएं खरीदेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करेंगे, और अपने-अपने देशों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में नीतियों व संस्थानों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

वैश्विकरण की अगली लहर "वैश्विक सर्वहितों" पर अधिक दबाव डाल सकती है, और रिपोर्ट चेतावनी देती है कि इन दबावों के कारण दीर्घकालिक प्रगति जोखिम में पड़ सकती है। राष्ट्रों को एकजुट होकर वैश्विक सर्वहितों से संबंध रखने वाले मामलों का सामना करना पड़ेगा - चाहे यह वैश्विक तापन कम करना हो, बर्ड फ्लू जैसे संक्रामक रोगों का फैलाव सीमित करना हो, या विश्व के मत्स्य उद्योग को अवक्षय से बचाना हो।

रिपोर्ट के अनुसार, पृथ्वी का तापन एक गंभीर खतरा है। उत्पादन में वृद्धि के कारण ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 2030 तक 50 प्रतिशत बढ़ सकता है, और यदि नीतियों में व्यापक परिवर्तन नहीं लाए गए तो 2050 तक यह बढ़कर दोगुना हो सकता है। इससे बचने के लिए, नीतियों के अंतर्गत "स्वच्छ" वृद्धि को प्रोत्साहित करना पड़ेगा ताकि उत्सर्जन उन स्तरों तक सीमित रह सके जिनपर आगे चलकर वायुमंडलीय सांद्रणों को स्थिर किया जा सके। इसके अलावा, निर्धन देशों को विकास सहायता की ज़रूरत होगी ताकि वे आने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल अपने को ढाल सकें, और कार्बन वित्त बाज़ार में उनकी प्रतिभागिता के लिए उन्हें समर्थन देना पड़ेगा।

लेखकों का निष्कर्ष है कि वैश्वीकरण की तीव्र गति ने अनेक चुनौतियां सामने की हैं, और न केवल राष्ट्रीय नीति-निर्माताओं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों के कंधों पर नया भार डाला है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह शिक्षा व बुनियादी संरचना में निर्धन-समर्थक निवेश करके, तथा अव्यवस्थित कर्मियों हेतु समर्थक साधनों को उपलब्ध कराकर, निर्धनों को भी वृद्धि की इस प्रक्रिया में शामिल करें। इन्हें कर्मियों को समर्थन देकर इनमें निवेश करना होगा – परिवर्तन के खिलाफ लड़ना नहीं, बल्कि परिवर्तन को बढ़ावा देना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सार्विक हितों पर मंडराते हुए खतरों का सामना करने के लिए रिपोर्ट मजबूत संस्थाओं की पुकार करती है। इसमें अधिक तथा बेहतर विकास सहायता की आवश्यकता रेखांकित की गई है। व्यापार की बाधाओं को कम करना बेहद ज़रूरी है चूंकि इससे निर्धन देशों और निर्धन लोगों के लिए नए मौके सृजित किए जा सकते हैं। श्री दादुश का कहना है कि "दोहा चक्र के विश्व व्यापार समझौतों को पुनर्जीवित करना और निर्धनों को लाभान्वित करने वाले समझौते पर एकमत होना अत्यंत ही आवश्यक हो चुका है।"

- ##### -

एम्बार्गो समाप्त होने से पहले पत्रकार इस सामग्री को वर्ल्ड बैंक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग सेंटर <http://media.worldbank.org/secure> पर देख सकते हैं।

जिन मान्यताप्राप्त पत्रकारों के पास पहले से पासवर्ड नहीं है वे <http://media.worldbank.org/> पर पंजीकरण प्रपत्र भरकर इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं।

एम्बार्गो समाप्त होते ही रिपोर्ट और संबंधित सामग्री <http://www.worldbank.org/gep2007> पर सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की इंटरएक्टिव संभावनाएं <http://www.worldbank.org/globaloutlook> पर पाई जा सकती हैं।